बाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(बाणिज्य विभाग)
बाणिज्य सचिव

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2015

सांसद 1798(अ).-राज्यों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समर्थनकारी वातावरण उपलब्ध कराने तथा भारत के निर्यातों को प्रोत्साहित करने में राज्यों को सहकार का रूप से वाणिज्य बनाने हेतु अवसरमा का सुझाव करने संबंधी उपायों के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा निर्देश दिन जातीय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद का गठन करने का निर्देश दिया गया है।

2. व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद में निम्नलिखित सदस्य नामित होंगे-

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम</th>
<th>सदस्य</th>
<th>सदस्य</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>केंद्रीय बाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में व्यापार एवं बाणिज्य के प्रभारी मंत्री</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>भारत सरकार के सचिव : बाणिज्य, राजस्व, नौकरी, बड़ा निर्माण एवं राजमार्ग, नागरिक सेवानिवृत्ति, अंतराष्ट्रीय नीति एवं संवर्धन, कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, पूर्व राउंडमॉपिंग, आर्थिक कार्य विभाग, एच.एस.एम.ए, कर का, पवारवारण</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>अधिकारी, रेलवे बोर्ड</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>सचिव / टीमसेट, नीति आयोग</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>डी.जी.एफ.डी</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>डी.जी.ई.डी</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>रिपोर्ट रिपोर्ट डेटा संचयन केंद्र</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>रिपोर्ट रिपोर्ट डेटा संचयन केंद्र</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>डी.जी.ई.डी</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>महासचिव, प्रिंसिपल, टीमसेट एवं एडिसन</td>
<td>सदस्य सचिव</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>बाणिज्य विभाग से संबंधित संगठन सचिव</td>
<td>सदस्य सचिव</td>
</tr>
</tbody>
</table>

अभाव आवश्यकता पड़ने पर निजी अधिकारी वा विदेश भाषा का नचाप कर सकते हैं।
3. व्यापार विकास एवं संबंधित परिषद हेतु संबंधित विचारार्थ विवाद निर्माणसूची होंगे—
   i. नियोजितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली बाधाओं और अवसरप्रद अवसरों का अर्थात समाधान करना।
   ii. अवसरप्रदत्मक बाधाओं का समाधान करना तथा संबंधित मंत्रालयों से समस्याहलारी व्यापक समर्थन के माध्यम से अवरोधों को हटाने वाली उपायों की सुविधाजनक बनाना।
   iii. राष्ट्रीय विदेश व्यापार मीमित के साथ राज्यों की नियोजित कार्यनीति का तालमेल बिना।
   iv. व्यापार सुगमता के संबंध में राज्यों में एक समान पद्धति बनाना तथा करों के निर्यात से बचना।
   v. राज्यों में शान्ति निर्माण को सुगम बनाना तथा 'निर्यात वंगृ' तथा अन्य स्थिरों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उनकी प्रतिस्पर्धितकता को बढ़ाना।
   vi. भारत के निर्यात प्रयासों में राज्यों की मानीदार बनाने हेतु अवसरप्रद का सुजन करना।

4. परिषद सभाशिष्टकृत प्रकृति की होगी तथा प्रक्रिया वर्ष में उसकी एक बैठक होगी। परिषद की बैठकें दिल्ली अथवा देश में कहीं भी आयोजित की जाएंगी। परिचार्य के रिकॉर्ड को अनुरक्षित किया जाएगा।

5. समयमंद सचिव, मुख्य धारा कार्यों के प्रथम परिषद का कार्य देखेंगे।

[मं 10/21/2015-एससी]
संजय चव्हाण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
NOTIFICATION
New Delhi, the 3rd July, 2015

S.O. 1798(E).—It has been decided to constitute the Council for Trade Development and Promotion with immediate effect in order to ensure a continuous dialogue with State Governments and UTs on measures for providing an International trade enabling environment in the States and to create a framework for making the States active partners in boosting India's exports.

2. The compositions of the Council for Trade Development and Promotion would be as below :-

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Position</th>
<th>Name</th>
<th>Chairperson</th>
<th>Members</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Union Commerce and Industry Minister</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Minister in-charge of Trade and Commerce in State Governments and UTs</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Members</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Chairman, Railway Board</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Members</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Secretary / CEO, Niti Ayog</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>DGIFT</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>DGEP</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Director Centre for WTO Studies</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Members</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Director RIS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>DG FIEO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>Secretary / Generals of FICCI, CII and ASSOCHAM</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>Concerned Joint Secretary In D/o Commerce</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Chairman can opt any other official or expert when required.
3. The Terms of Reference for the Council for Trade Development and Promotion would be as follows:
   i. To provide a platform to State Governments and UTs for articulating their perspectives on trade policy;
   ii. To provide a platform to Government of India for apprising State Governments and UTs about international developments affecting India's trade potential and opportunities and to prepare them to deal with evolving situation;
   iii. To help State Governments develop and pursue export strategies in line with national Foreign Trade Policy;
   iv. To provide a platform for deliberation on the need for infrastructure relevant for promoting trade and for identification of impediments and infrastructure gaps which adversely affect India's exports;
   v. To facilitate a mechanism for discussion on operationalization of trade infrastructure.

4. The Council will be recommendatory in nature and will meet at least once every year. The meetings of the Council will be held at Delhi or anywhere in the country. Records of the discussion will be kept.

5. The Council will be served by the Joint Secretary, in-charge of mainstreaming work.

[No. 10/21/2015-SC]

SANJAY CHADHA, Jr. Secy.